भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारगा EXTRAORDINARY

42611219

भाग II—सण्ड ३—उप-सण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 353]

नई विल्ली, संगलबार, जुलाई 5, 1988/आषाव 14, 1910 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 1988/ASADHA 14, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

ग्रधिम् धना

नई दिस्ती, 5 ज्लाई. 1988

का.आ. 676(श्र).--संविधान के अनुक्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रवस्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यूशन भारत गरकार (कार्य श्राखंडन) निवम, 1961 का और संगोधन करने के जिए निम्नविधित निवम बनाने हैं, प्रचीत्:---

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य भावंटन) (एक सी सतानवेदा मंशोधन) नियम. 1988 है।
 - (2) ये नुस्तः प्रवृत्तः होंगे।
- 2 भारत गरकार (कार्य श्राबटन) नियम, 1961 का द्विताय अनुसूची में,----
 - (क) "क्वांप मंत्रालय" शीर्षक के अज्ञान "क कृषि और सहकारिता विभाग" उपशिक्त में,----
 - (i) प्रविद्धिः 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविद्धिः रक्षी जाए.मर्थात् :--
 - "5. वे उचीग जिनके लिए संसव ने विधि द्वारा घोषणा भी है कि उन पर संघ का नियंत्रण घोकहित में समीचीन है, बहुत तक जहां तक वे निम्नतिखित से संबद्ध है :----

- (क) क्रिप उद्योगों (मणीनरीं, उर्बरक, बीज और पणु खाय मिंहत) का इस परिसीमा के साथ कि क्रिप उद्योगों (मणीनरी और उर्वरक मिंहत) के विकास के यारे में क्रिप और सहकारिता विभाग के कृत्य मांगों के शाकलन और लक्ष्यों के नियतन से स्रधिक न हों।
- (ख) गल्क लाख उद्योग।";
- (ji) प्रविष्टि ? का शोप किया जाएगा।
- (ख) "स्वाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रापय" मीर्षक के घ्राधीन "क. स्वास विभाग" उपगीर्षक में प्रविद्धि 6 के स्यान पर निम्न-लिखिन प्रविद्धि रखी ज,एगी, ध्रयांत् :---
- "6. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में भमीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पार्करा उद्योग (जिसके प्रस्तर्गत गृह और खांडकारी प्राप्ते हैं) से हैं।";
- (ण) "खास और नागरिक पूर्ति संत्रालय" शोर्थक और उसके मधीन प्रविष्टियों के पश्चाल् निम्नलिखित शोर्थक और प्रविष्टियों अंतःस्थापित की काएंगी :---

"खाध प्रसंस्करण उद्योच मंत्रालय

 वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विक्रि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण सोकिह्स में समीचीन है, वहां तक, जहां तक वे निम्नलिखित से सम्बद्ध है—

- (क) कुछ कृषि जल्पादो (दुग्ध, चूर्ण, शिशु हुग्ण प्राहार, माल्ट मिश्रित दुग्ध भाहार, संघानित दुग्ध, घो और प्रत्य देशे , उस्ताद) मुक्कुट और अंदे, मांस और मांस जल्पादों का संसाधन और प्रणीतन;
- (ख) मछलियों का संसाधन (जिसके श्रन्तर्गत डिक्बों में बन्द करना और हिमीकरण भी सम्मिलित है);
- (ग) मत्स्य ग्रांसाधन उथोग के लिए विकास परिषद की स्थापना और उसकी प्रबंध व्यवस्था;
- (घ) महस्य संसाधन उद्योगों को तकनीकी सहायता और सलाह;"
- (ङ) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिनके अन्तर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण आते हैं); और
- (च) खाग्राम पिमाई उद्योग।
- राज्य क्षेत्रीय समृद्र से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र (जिसके अन्तर्ग न गहरे समृद्र में मछती पकड़ने का स्थान बस्बई है)।
- 3. उन उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और महायता जो इबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाध), नावते के धाहार विस्कुट, मिष्ठान (जिसके धन्तर्गन कोको संसाधन और चाकतेट धनाना भी धाना है), माल्ट्सार पृथककृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन धहार, स्तनय त्याग धाहार और उत्सारित (एक्सट्डेड) खादा, उत्पाद (जिसके प्रन्तर्गत तत्काल खाने योग्य। अन्य आहार प्राते है) से संबंधित है।
 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशिष्ट पैकेजिय;
 - 5. बियर जिसके अन्तर्गत अनएलकोहानी बियर भी है।
 - ऐसे एल्कोहाली पेय जिनका ग्राधार शीरे पर न हो।
 - 7 वास् मिश्रित जन/मृतम पेव ।";
 - (अ) "उद्योग मंत्रापय" शीर्षक के प्रधीन,---
 - (1) "क. औद्योगिक विकास विभाग" उपशीर्षक मे प्रविष्ट ६ के स्थान पर निम्नलिखिन प्रविष्टि रखी जाएगी, भर्यात्:---
 - "6. सभी ज्ञद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जिनमें किसी प्रत्य विभाग के अन्तर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते।';
 - (2) "ग. रसायन और पट्टो रमायन विभाग" उपशीर्षक में प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्निलिखण प्रविष्टि रखी जाएगी, प्रयोत्:---

्र एलकोहरा--औद्योगिक और पेय (ऐसे एल्कोहानी पेय को छोड़ कर जिनका ग्राद्यार कीरे पर न हो) भारतीय प्रवर एलकोहल ग्रिधिनियम, 1948 (1948 का. 22) सहिन'।''।

> ध्रार, ेे वेंकटरामन, राष्ट्रपति

[फा.सं. 74/2/1/88-मन्नि.] वीपक वास गुप्ता, संयुक्त सणिव,

CABINET SECRETARIAT NOTIFICATION

New Delhi the 5th July, 1988

S. O.676(E):—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution the President hereby makes the following rules

further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety seventh Amendment) Rules, 1988.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—
 - (a) under the heading "MINISTRY OF AGRI-CULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPAR TMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBITAG)",...
 - (i) for the entry 5, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "5. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest; as far as these relate to:—
 - (a) Development of agricultural industries including machinery, fertilizer, seeds and cattle-feed with the limitation that in regard to the development of agricultural industries, including machinery and fertilizer, the functions of the Department of Agriculture & Cooperation (Krishi Aur Sahkarita Vibhag) do not go further than the formulation of demands and the fixation of targets;
 - (b) Shellac Industry.";
 - (ii) entry 7 shall be omitted.
- (b) under the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" under sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "6. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as there relate to Sugar Industry (including development of gur and khandsari).";
- (c) after the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF FOOD PROCESSING IN-DUSTRIES (KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG MANTRALAYA)

- 1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by Law to be expedient in public interest, as far as these relate to:—
- (a) Processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, infantmilk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Poultry and eggs, Meat and Meat products;
- (b) Processing of fish (including canning and freezing);
- (c) Establishment and servicing of Development Council for fish processing industry;
- (d) Technical assistance and advice to fish processing industry;
- (e) Fruit and Vegetable processing industry (including freezing and dehydration); and
- (f) Foodgrain milling industry.
- 2. Fishing and fisheries beyond territorial waters (including Deep-Sea Fishing Station, Bombay).
- 3. Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oil-seeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food preducts (including other ready-to-eat foods).
- 4. Specialised packaging for food processing industry.

- 5. Bee: including non-alcoholic beer.
- 6. Alcoholic drinks from non-molasses base.
- 7. Aerated waters/soft drinks.";
- (d) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)",---
 - (i) under sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", for entry 6, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "6. Planning, development and control of and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department.";
 - (ii) under sub-heading "C. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VI-BHAG)", for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "4. Alcohol—Industrial and potable (excluding-Alcoholic drinks from non-molasses base) including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948)."

R. VENKATARAMAN, PRESIDENT,

[F. No. 74/2/1/88-Cab.] D. DAS GUPTA, Joint Secy, to the Cabinet.